



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Thursday, 29th August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 04 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	भारत और रूस ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए
Page 04 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	भारत ने 73,000 SIG 716 राइफलों के लिए दोबारा ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए; 2025 के अंत तक डिलीवरी
Page 07 Syllabus : GS 3 : आपदा और आपदा प्रबंधन	जलवायु अनुसंधान को आपदा प्रबंधन में बदलने की रणनीति चाहता था
Page 07 Syllabus : GS 2 : सामाजिक न्याय	'भारतीय व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की उच्च मात्रा'
योजना समाचार में	प्रधानमंत्री जन धन योजना
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : संपादकीय विश्लेषण:	भारत की तपेदिक विरोधी लड़ाई को तेज करना
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: शंघाई सहयोग संगठन



THREE HINDU Daily News Analysis

Page 04: GS 2: International Relations

भारत और रूस ने 2025-26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन पर अपने संयुक्त आयोग के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अंतरिक्ष निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

📦 यह समझौता पिछले सहयोगों पर आधारित है और इसका उद्देश्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है, जिसकी अगली बैठक भारत में निर्धारित है।

भारत-रूस आपातकालीन प्रबंधन सहयोग

🔸 कार्य योजना समझौता

o भारत और रूस ने 2025-26 के लिए आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी-भारतीय आयोग के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए।

o इस समझौते पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और रूसी नागरिक सुरक्षा, आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों के उन्मूलन मंत्री ने हस्ताक्षर किए।

ऐतिहासिक संदर्भ

o यह समझौता दिसंबर 2010 से अंतर-सरकारी समझौते (IGA) और 2013 में सहयोग के लिए भारत-रूस संयुक्त आयोग की स्थापना सहित पिछले सहयोगों का अनुसरण करता है। o इस आयोग की पहली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी।

सहयोग के क्षेत्र

- o अंतरिक्ष निगरानी प्रौद्योगिकियाँ: जोखिम पूर्वानुमान और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।
- o आपदा प्रतिक्रिया अनुभव: बडे पैमाने पर आपदाओं के प्रबंधन में अनुभवों का आदान-
- o प्रशिक्षण: अग्नि और बचाव विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में सहयोग।

भविष्य की योजनाएँ और उद्देश्य

o कार्य योजना का उद्देश्य द्विपक्षीय प्रयासों को बढाना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में सुधार करना और आपातकालीन तैयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया और योजना में क्षमता निर्माण को बढावा देना है।

o समझौते का उद्देश्य मौजूदा ढाँचों को उन्नत करना और दोनों देशों में आपातकालीन प्रबंधन क्षमताओं को बढाने में आपसी सहायता का समर्थन करना है।

India and Russia sign a working plan to handle emergencies

The Hindu Bureau NEW DELHI

India and Russia on Wed-nesday signed the working plan of the Joint Russian-Indian Commission on the Cooperation in the Field of Emergency Management for 2025-26.

Union Minister of State for Home Nityanand Rai and Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Minister of the Russian Federation for Civil Defence, Emer-gencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (EMERCOM of Russia), signed the agree-ment in Moscow.

ment in Moscow.

Both the countries agreed to implement the plan during 2025-26, and decided to continue exchange of the best practices and lessons learnt in the field of disaster management.

"This meeting is significant to draw a strategy for

cant to draw a strategy for executing the previous agreements between India agreements between India and Russia, such as, Inter-Governmental Agreement (IGA) for cooperation in the field of Emergency Management in December, 2010, and Regulation to establish the Indo-Russian Joint Commission for Cooperation (2013) in prevention and elimination of consequences of emergency situations," a statement from the Union Home Ministry said.

The first meeting of the commission was held in

commission was held in New Delhi in 2016. "Within the overall fra-

"Within the overall fra-mework of cooperation, the three specific issues were deliberated in the meeting – use of space monitoring technologies for risks forecasting and emergency response, ex-change of experiences of responding to large-scale disasters, and cooperation in the field of training of fire and rescue specialists," fire and rescue specialists,'

in the held of training of fire and rescue specialists," the statement said.

It was decided that the next meeting of the commission will be held in India in 2026. This working plan will give added impetus to the bilateral efforts and pave the way for upgradation, mutual assistance in enhancing early warning systems and capacity building of both the countries in emergency preparedness, prevention, response and planning, the Ministry said.



UPSC Prelims PYQ: 2019

प्रश्न: हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 'परमाणु क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों की प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना' नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?

- (a) जापान
- (b) रूस
- (c) यूनाइटेड किंगडम
- (d) संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: b)

GEOIAS —It's about quality—

Page 04: GS 2: International Relations



THE WELL HINDU Daily News Analysis

 भारतीय रक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में सिग सॉयर, यू.एस. से
 73,000 SIG 716 राइफलों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी डिलीवरी 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है।

ये राइफलें फ्रंटलाइन काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए स्वदेशी INSAS राइफलों की जगह लेंगी।

India signs repeat order for 73,000 SIG 716 rifles; deliveries by 2025-end

Dinakar Peri

NEW DELHI

The Ministry of Defence has signed a repeat order for 73,000 SIG 716 rifles from Sig Sauer of the U.S. and deliveries are expected to completed end-2025.

"The contract signed in June 2024 and delivery is within 18 months of contract," a defence official said. The Army has earlier procured and inducted 72,400 SIG 716 rifles through fast-track procurement under ₹700-crore contract signed in February 2019.

"We are proud to be a partner in the modernisation effort of the Indian Ar-



The Army has inducted 66,400 of the 72,400 SIG 716 assault rifles procured under a ₹700-crore deal in February 2019. FILE PHOTO

my, and prouder still that the SIG 716 rifle achieves the Ministry of Defence's modernisation goals with the second largest Army in the world," Ron Cohen, president and CEO, Sig Sauer, said in a statement issued on August 26. "Since the initial fielding of the SIG 716, we have received phenomenal enduser feedback on the performance and reliability of the platform."

The successful fielding

and overwhelming soldier acceptance led to this follow-on award for an additional 73,000 rifles, the company added.

The Army has for long been looking to replace the indigenous INSAS (Indian National Small Arms System) rifles in use with a modern rifle.

The Army has inducted 66,400 of the 72,400 SIG 716 assault rifles procured under the deal in February 2019 and these have been provided to frontline troops involved in counterinsurgency operations.

The SIG 716, weighing 3.82 kg, has an effective range of 600 m and is more capable and reliable than the INSAS in use.

SIG 716 राइफलें:

- 🔸 SIG 716 एक मॉड्यूलर, गैस-संचालित, अर्ध-स्वचालित राइफल है जिसे Sig Sauer द्वारा निर्मित किया गया है।
- इसका वजन 3.82 किलोग्राम है, इसमें 16 इंच की बैरल और 600 मीटर की प्रभावी रेंज है।
- ▶ विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिज़ाइन किया गया, यह एक फ्री-फ़्लोटिंग हैंडगार्ड, एडजस्टेबल स्टॉक और सहायक उपकरण के लिए पिकाटनी रेल से सुसज्जित है।
- राइफल एक शॉर्ट-स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम का उपयोग करती है, जो विभिन्न परिस्थितियों में इसकी स्थायित्व और प्रदर्शन को बढाती है।



THE HINDU Daily News Analysis

▶ INSAS राइफलों की तुलना में, SIG 716 बेहतर सटीकता, विश्वसनीयता और आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करता है, जो इसे मानक और आतंकवाद विरोधी दोनों तरह के ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

इसके मजबूत प्रदर्शन के लिए इसे वैश्विक स्तर पर कई सैन्य बलों द्वारा अपनाया गया है।

UPSC Mains PYQ: 2019

प्रश्न: 'भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में टकराव का कारण यह है कि वाशिंगटन अभी भी अपनी वैश्विक रणनीति में भारत के लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ पाया है, जो भारत के राष्ट्रीय आत्म-सम्मान और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके।' उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए।





THE MEAN HINDU Daily News Analysis

Page 07: GS 3: Disaster and disaster management

भारत बेहतर आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलापन प्रयासों के माध्यम से अपने विविध प्राकृतिक खतरों का समाधान कर रहा है। चुनौतियों में बेहतर स्थानीय पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता शामिल है।

• मौसम की तैयारी बढ़ाने में अनुसंधान को व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ जोड़ना और क्षेत्र-विशिष्ट आपदा प्रबंधन

समाधानों के लिए क्षमता निर्माण करना शामिल है।

Wanted: a strategy to turn climate research into disaster management

Climate researchs goals were once research papers and PhDs, but now it must meet people's needs by bringing science to society; govts, and disaster management agencies are depending on it, and sector-specific extension agents are necessary to bridge the research and administrative enterprises

Raghu Murtugudde

ndia is increasingly aware of the multiple location-specific natural hazards it is facing, each with a rapidly evolving risk landscape. se risks are a combination of weather nts, vulnerabilities of the local events, vulnerabilities of the local population, and their exposure. Risks are best managed and mitigated with well-planned responses. The National Disaster Management Authority (NDMA) deserves the kudos it receives for its response to disasters and its help reducing their mortality and damage. But it also contends with many knowledge gaps and parties in improving its operations to mark the most of the proving its operations to make the most proving its operations to make the most proving its operation to the most proving its operation to make the most proving its operation to make the most proving its pr

climate resilient.

Never cease to surprise

Most regions of india know by now to expect weather extremes in all seasons, including heatwayes, wildines, heavy rains, landsides, droughts, and cyclones. The india Meteorological Department (IMI) tries to keep pace by improving its forecasts of all weather hazards, even if they tend to not be as local (in scale) as required to plan disaster responses. Sallis can always improve.

Academic institutions and government research facilities play an important role in understanding, and improving predictions. They also continue to develop and implement moved approaches to downscaling global, coarse-resolution forecasts to hyperfocal scales for specific sectors.

Climate chance manifests locally as

forecasts to hyperfocal scales for specific sectors.

Climate change manifests locally as cooler and warmer temperature trends over northern-central and peninsular India, respectively. But this hardy means we are spared from heatwaves. Similarly, rainfall extremes now occur not only during the monsoon season of June to post-monsoons. Land that is weakly supported suffers more landslides as a result. Wildfires have also been reported to be on the rise.

Exacerbated to weather extremes
Vulnerability isn't entirely natural.
Thanks to India's population and
economic growth, people are moving into
more unsafe regions and establishing
informal housing on unstable slopes and
flood prone areas. The more exotic of
these places have invited more tourists, as these places have invited more tourists, a a result of which the state sets up more infrastructure in these locales and encourages other economic activities, such as replacing forest cover with cash crops and plantations.

The recent landslides in Wayanad put ch a dangerous mix of factors on ful

such a dangerous mix of factors on full display.

Taken together, vulnerability is a combination of poverty and high population density with poor infrastructure in some places and wealth and unsafe development in others. Insurance coverage and/or policies could also be creating a moral hazard by incentivising people to increase their exposure to climate risks.

Ineffective translation
India continues to invest heavily in climate research, forecasts, and climate services.
Climate services translate forecasts into support for decision-making in agriculture, water and energy resources, healthcare, transportation, and other sectors. But the uptake of this information has been creamatably fow because as each section of the researchers and the properties of the section of the research services. The transportation, and other sectors. But the uptake of this information has been creamatably fow because as a few sections of the research services and other corps.

The researchers can use this feedback to transportation, and other sectors and other corps. The researchers can use this feedback to the present of the researchers and other corps. The researchers can use this feedback to the present of the researchers and other corps. The researchers can use this feedback to the present of the researchers can use this feedback to the present of the researchers can use this feedback to the researchers can use this feedback to the researchers can use this feedback to the present of the researchers can use this feedback to the researchers. The researchers can use this feedback to the



Aroad damaged by a landslip triggered by heavy rair right skills to use it.

Academia and many private ventures continue to push the hims of translating the IMT's forecasts into hyperical scales and to improve the skills to delive which the properties of the scales and skill-levels required, operationalising specific products are generated at the scales and skill-levels required, operationalising them or providing them in a timely and routine manner remains a major hurdle. Two examples liststrate this problem.

(b) Irrigation advisories: Weather forecasts frequently are translated to farm-scale information to manage irrigation from days to 5 and water arrangement information for up to 14 days. Experts combine farmers' inputs on their irrigation

from days 1 to 5 and water arrangement information for up to 14 days. Experts combine farmers' inputs on their irrigation practices with data of soll properties, crop types, water requirements, and crop stress oth art anifall forceasts can inform decisions about whether there is sufficient water for irrigation and what the schedule should be.

The conformation of the schedule should be the stress of the stress of the schedule should be.

The conformation of the schedule should be the schedule should be the schedule should be the schedule should be schedule schedule should be s

Climate services translate forecasts into support for decision-making. But the uptake of this information has been low because it is either not as location- or sector-specific as it needs to be or there are not many people with right skills to use it

ater-logging. Again, neither an academic setup nor the Again, feeline an academic setup for more an exademic setup for the structure of urban governments allows us to translate downscaled forecasts to urban flood management and flood risk mitigation completely.

solocation—or sector-specific as it needs to be or there are not many people with right skills to use it needs to be or there are not many people with right skills to use it needs to be or there are not many people with right skills to use it needs to be concerned and a many people with right skills to use it and a many people with right skills to use it needs to be concerned and a many people state of the concerned and the process of the process of







जागरूकता और चुनौतियाँ

- भारत को स्थान-विशिष्ट प्राकृतिक खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हीटवेव, जंगल की आग, भारी बारिश,
 भूस्खलन, सूखा और चक्रवात शामिल हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया और मृत्यु दर और क्षिति को कम करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
- अपनी उपलब्धियों के बावजूद, NDMA मौसम की तत्परता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए अपने संचालन में सुधार करने में ज्ञान की कमी और बाधाओं से जूझ रहा है।

मौसम की चरम सीमाएँ और जलवायु परिवर्तन

- भारतीय क्षेत्रों में सभी मौसमों में मौसम की चरम सीमाएँ देखी जाती हैं, जिसमें हीटवेव, जंगल की आग और पारंपिरक मानसून अविध के बाहर बारिश की चरम सीमाएँ जैसी घटनाएँ होती हैं।
- 📦 जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में उत्तर-मध्य भारत में ठंड का रुझान और प्रायद्वीपीय भारत में गर्मी का रुझान शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, हाल ही में जंगल की आग और भूस्खलन में वृद्धि देखी जा रही है।

भेद्यता कारक

- जनसंख्या और आर्थिक वृद्धि के कारण भेद्यता और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग असुरिक्षत क्षेत्रों में चले जाते हैं और अस्थिर या बाढ-ग्रस्त क्षेत्रों में अनौपचारिक आवास बनाते हैं।
- इन क्षेत्रों में पर्यटन और बुनियादी ढाँचे के विकास में वृद्धि इस समस्या में योगदान करती है, साथ ही वन क्षेत्र को नकदी फसलों से बदलना भी समस्या में योगदान देता है।

जलवायु अनुसंधान का अप्रभावी अनुवाद

- भारत विभिन्न क्षेत्रों को सहायता देने के लिए जलवायु अनुसंधान और सेवाओं में भारी निवेश करता है, लेकिन अपर्याप्त स्थान- या क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी और इसका उपयोग करने के लिए अपर्याप्त कौशल के कारण इसका उपयोग कम रहता है।
- वैश्विक पूर्वानुमानों को हाइपरलोकल स्केल पर कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इन पूर्वानुमानों को क्रियान्वित करना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

कार्यान्वयन मुद्दों के केस स्टडी

सिंचाई सलाहः

- o मौसम पूर्वानुमान का उपयोग खेत-पैमाने पर सिंचाई सलाह प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो फसल की उपज को प्रभावित किए बिना 30% तक पानी बचा सकता है।
- o बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपयोग और प्रतिक्रिया संग्रह के लिए स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संगठनों और किसान संगठनों की आवश्यकता होती है। विस्तार एजेंसियों और वित्त पोषण संरचनाओं की वर्तमान कमी प्रगति को बाधित करती है।

शहरी बाढ पूर्वानुमान:

o प्रभावी शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए वर्षा पूर्वानुमानों को कम करने और जल निकासी पंपों, यातायात नियंत्रण और अन्य शहर के कार्यों के समन्वय की आवश्यकता होती है।



o नगर पालिकाएं सेंसर और मौसम डेटा का उपयोग करती हैं,

लेकिन व्यापक बाढ़ प्रबंधन अपर्याप्त अनुसंधान-से-संचालन प्रणालियों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी से बाधित है।

शोध से लेकर संचालन तक

o जलवायु अनुसंधान को अकादिमक लक्ष्यों से प्रभावी आपदा प्रबंधन और जलवायु लचीलेपन के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने की आवश्यकता है।

o शोध और परिचालन आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट विस्तार एजेंटों की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाधान स्थानीय संदर्भों के अनुरूप हों।

o स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रभावी शोध-से-संचालन प्रणाली विकसित करने के लिए निरंतर वित्तपोषण और क्षमता निर्माण आवश्यक है।

निष्कर्ष

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का विकास टिकाऊ और सुरिक्षत है, व्यावहारिक अनुप्रयोगों के साथ अनुसंधान के बेहतर एकीकरण के माध्यम से मौसम की तत्परता और जलवायु लचीलेपन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- क्षेत्र-विशिष्ट विस्तार एजेंटों को प्रशिक्षित करना और तैनात करना जो स्थानीय भाषाओं में संवाद कर सकते हैं और सांस्कृतिक कारकों का प्रबंधन कर सकते हैं, प्रभावी आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।.

UPSC Mains PYQ: 2019

प्रश्न: आपदा के प्रभावों और लोगों के लिए इसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक आवश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता को कैसे और किन तरीकों से चिह्नित किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें।





Page 07: GS 2: Social Justice - Health

हाल ही में किए गए शोध से पता चला है कि भारत में व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पॉलीइथिलीन और पॉलीकैप्रोलैक्टोन सहित हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक शामिल हैं।

- "पर्यावरण के अनुकूल" या "प्राकृतिक" होने के दावों के बावजूद, कई उत्पाद प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिससे
 पर्यावरण और स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम होता है।
- 📦 माइक्रोप्लास्टिक संदूषण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कम करने के लिए बेहतर नीतियों की आवश्यकता है।

माइक्रो प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है

🔸 माइक्रोप्लास्टिक की परिभाषा

o माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के छोटे प्लास्टिक कण होते हैं। इनमें माइक्रोबीड्स शामिल हैं, जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है और अक्सर फेस वॉश और स्क्रब जैसे व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक के बढते उपयोग

- o व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद: पॉलीइथिलीन (पीई) और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर फेस वॉश, स्क्रब और शॉवर जैल में एक्सफ़ोलीएटिंग एजेंट के रूप में और घटक वितरण को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- o फार्मास्यूटिकल्स: पॉलीकैप्रोलैक्टोन जैसे बायोप्लास्टिक का उपयोग उनके एंटी-एजिंग और जीवाणुरोधी गुणों के कारण दवा वाहक के रूप में किया जाता है।
- ⇒ उपभोक्ता वस्तुएँ: माइक्रोप्लास्टिक सफाई एजेंटों और सौंदर्य प्रसाधनों सिहत विभिन्न उत्पादों में पाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर "प्राकृतिक" या "पर्यावरण के अनुकूल" जैसे लेबल के तहत रखा जाता है, जो भ्रामक हो सकता है।

माइक्रोप्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव

- पर्यावरण प्रदूषण: माइक्रोप्लास्टिक जल निकायों और मिट्टी को दूषित करते हैं, जिससे जलीय और स्थलीय दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है।
- वन्यजीवों पर प्रभाव: समुद्री जीव माइक्रोप्लास्टिक को निगल लेते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखलाओं में व्यवधान होता है और वन्यजीवों को नुकसान पहुँचता है।
- स्वास्थ्य जोखिम: माइक्रोप्लास्टिक मानव ऊतकों, जैसे मस्तिष्क, रक्त, फेफड़े और पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, जिससे संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएँ बढ जाती हैं।
- ➡ जैव संचय: माइक्रोप्लास्टिक मानव और पश् शरीर में जमा हो सकते हैं, जिससे अज्ञात दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं।
- ग्रीनवाशिंग: "ऑर्गेनिक" या "पर्यावरण के अनुकूल" के रूप में लेबल किए गए उत्पादों में अभी भी माइक्रोप्लास्टिक हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं को उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में गुमराह करते हैं।
- जटिल प्रयास: ग्रीनवाशिंग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को कमजोर करता है और उत्पाद पारदर्शिता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की खोज को जटिल बनाता है।

UPSC Mains PYQ: 2019

प्रश्न: विकास पहलों और पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव से पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बहाल किया जा सकता है?



Scheme In News : Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

28 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) एक दशक पूरा कर लेगी, जो वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।



प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के बारे में:

- 🔸 शुरू होने की तिथि: 28 अगस्त, 2014
- उद्देश्य: बैंकिंग/बचत खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन सिहत वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती पहुँच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढावा देना।
- महत्वः यह कई सरकारी आर्थिक पहलों के लिए आधारशिला है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सुविधा
 प्रदान करता है।

पात्रताः

- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिंग आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने पीएमजेडीवाई खाते को संचालित करने के लिए अपने कानूनी अभिभावकों से सहायता की आवश्यकता होगी।



जन धन खाता:

- कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक मित्र) आउटलेट के साथ खाता खोल सकता है।
- पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खाते शून्य शेष राशि के साथ खोले जा सकते हैं। हालाँकि, यदि खाताधारक चेकबुक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे न्यूनतम शेष राशि के मानदंड को पूरा करना होगा।
 ० इस योजना के तहत खाताधारकों को एक RuPay डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग नकद निकासी के लिए सभी ATM में किया जा सकता है।

योजना की मुख्य बातें:

- o जीरो-बैलेंस खाते: बिना किसी न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता के खाते खोले जा सकते हैं।
- o RuPay डेबिट कार्ड: अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ एक निःशुल्क RuPay डेबिट कार्ड प्रदान करता है।
- o दुर्घटना बीमा: ₹2 लाख तक।
- ० जीवन बीमा: पात्र पहली बार खाताधारकों के लिए ₹30,000 तक।

ओवरङ्गाफ्ट सुविधाः

- o प्रति परिवार एक खाते में ₹10,000 तक उपलब्ध है, साथ ही छह महीने तक संतोषजनक खाता गतिविधि के बाद ₹5,000 का अतिरिक्त ऋण भी दिया जाता है।
- o कवरेज फोकस: 6% खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, जिनमें 55.6% खाताधारक महिलाएँ हैं।
- o बैंकिंग पहुँच: 95% बसे हुए गाँवों में 5 किमी के दायरे में बैंकिंग सुविधाएँ हैं।

हालिया घटनाक्रम:

🟓 खातों में वृद्धिः

- o मार्च 2015 में खातों की संख्या 72 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ हो गई।
- o पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि ₹15,670 करोड़ (मार्च 2015) से बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़ (अगस्त 2024) से अधिक हो गई।
- o वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य अतिरिक्त 3 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोलना है।
- o चालू खाते: देश में 173 करोड़ CASA खातों में से 53 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खाते हैं, जिनकी परिचालन दर 80% है।



Page: 08 Editorial Analysis Sharpening India's anti-tuberculosis fight

he omnipresence of tuberculosis (TB) in the pages of history and literature is testimony to how the disease has plagued generations across the world and continues to be a major problem even today. India bears over a quarter of the global TB burden. Political will in India has helped drive a great deal of progress in the fight against the disease. For example, in 2023, addressing the big challenge of 'missed' TB cases, 25.1 lakh patients were diagnosed in India as having TB, highlighting strengthened case finding efforts. However, as we work toward the goal of TB elimination - the Prime Minister has urged citizens to work towards TB elimination we must look to innovate and deploy proven technologies and tools at our disposal.

Regimens and issues

The first low-hanging fruit that I believe must be invested in urgently is new shorter regimens for drug-resistant TB. It has been encouraging to learn that India will soon introduce the World Health Organization (WHO)-recommended shorter regimen for drug-resistant TB. The current regimens on offer are long and arduous, requiring patients to consume nearly 13 to 14 tablets every day if they are on the shorter nine to 11-month regimen, or four to five tablets every day if they have been put on the 18 to 24 month longer regimen. The treatment is physically and psychologically draining and has severe side effects, such as loss of hearing, and even psychosis.

Moreover, a problem with such an extended treatment regimen that requires regular visits to a TB clinic for nearly two years is loss of



Dr. Randeep Guleria

Chairman of the Institute of Internal Medicine and Respiratory and Sleep Medicine at Medanta, Gurugram, and a former Director of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

With the availability of game-changing new treatments, India must recast its TB-elimination programmes

employment, driving many families into poverty.

In 2022, WHO recommended the shorter, safer and more effective regimens called BPaL/M for all drug-resistant TB patients, and there is a lot of recent data that show this regimen to be more effective with better compliance. With only three to four tablets every day, patients can complete their treatment within six months, with minimal side effects. The success rates of this regimen are also reported to be higher - 89% as compared to the 68% treatment success rate reported in the country in the 2023 India TB Report. Given its efficacy, close to 80 countries around the world have already procured the BPaL/M regimen and about 20 of the highest burden countries are already rolling it out.

Research indicates that savings from implementing this regimen will be between 40% to 90% of the cost of current treatment regimens, and that an immediate transition to BPaL/M could result in an annual saving of approximately \$740 million (or approximately ₹6,180 crore) for health systems globally. This is a more effective and safer solution to treat drug-resistant TB and we must work on expediting access to this regimen to all eligible patients across the country.

Making the best use of new treatments

The next question is this. How do we go about diagnosing more people with TB so that they can benefit from these game-changing new treatments? The answer lies in making sure that we are screening and testing quickly and efficiently to reduce delays in accurate diagnosis. For this, a proactive approach is essential. It is time we modernised and used health datasets,

which include GIS mapping, to identify vulnerable populations such as those with comorbidities (for example, malnutrition, diabetes and HIV), former COVID-19 patients, and at-risk communities in slums, prisons, or those who are homeless. Targeted multi-disease focused screening drives can then be conducted to detect TB cases early, even among those without typical symptoms.

In fact, recent evidence highlights that a significant number of people with pulmonary (i.e., lung) TB may not exhibit recognisable symptoms such as cough, fever, weight loss, or night sweats. The National TB Prevalence Survey (2019-21) highlights the importance of chest X-rays, which detected 42.6% of cases that would have otherwise been missed. Leveraging advancements in technology, portable X-ray machines equipped with AI-driven tools can significantly reduce diagnostic delays, especially in remote and under-resourced areas.

Further, there is a critical need to expand the use of rapid molecular tests over less sensitive microscopy methods for faster detection and drug resistance profiling. This shift is crucial in promptly identifying TB cases and determining appropriate treatment options. In short, by proactively identifying at-risk populations and investing in and leveraging advanced/innovative diagnostic technologies, we can improve TB detection rates, reduce delays, and enhance treatment outcomes.

As we look to eliminate tuberculosis and and make our country TB-free, prioritising these essential areas will be critical as these will be an investment in a healthier future for all of us.

Paper 02: सामाजिक न्याय – स्वास्थ्य

UPSC CSE (M) GS-2 : 2021) "कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" (150 w/10m)

UPSC Mains Practice Question भारत में दवा प्रतिरोधी तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें, जिसमें कम समय की उपचार पद्धति और नवीन नैदानिक दृष्टिकोंण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। (150 w /10 m)





संदर्भ :

- यह लेख भारत में तपेदिक (TB) के खिलाफ चल रही लड़ाई पर चर्चा करता है, जो वैश्विक टीबी बोझ का एक चौथाई से अधिक है।
- यह दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए कम समय में अधिक प्रभावी उपचार, बेहतर निदान विधियों और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य के लिए प्रारंभिक पहचान के लिए अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।

तपेदिक: एक सतत चुनौती

- तपेदिक (टीबी) एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, भारत में दुनिया के 25% से अधिक टीबी के मामले हैं।
- राजनीतिक प्रतिबद्धता से प्रेरित प्रगित के बावजूद, टीबी को खत्म करने के लिए अभिनव समाधान और मौजूदा तकनीकों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है।
- 2023 में, भारत में 25.1 लाख टीबी मामलों का निदान किया गया, जो मजबूत केस-फाइंडिंग प्रयासों का संकेत देता है।

वर्तमान उपचार व्यवस्था और चुनौतियाँ

- दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए मौजूदा उपचार लंबे और कठिन हैं, रोगियों को कम समय (9-11 महीने) के लिए प्रतिदिन
 13-14 गोलियां या लंबे समय (18-24 महीने) के लिए प्रतिदिन 4-5 गोलियां लेने की आवश्यकता होती है।
- ये उपचार शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले होते हैं, जिनमें गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे सुनने की क्षमता में कमी और मनोविकृति।
- उपचार की लंबी अविध के कारण नौकरी छूट जाती है, जिससे पिरवार गरीबी में चले जाते हैं, जिससे अधिक कुशल उपचार की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

नया छोटा उपचार: BPaL/M

- ▶ WHO ने 2022 में दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए BPaL/M नामक एक छोटा, सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार की सिफारिश की है।
- ▶ BPaL/M उपचार के लिए प्रतिदिन केवल 3-4 गोलियों की आवश्यकता होती है, जिसमें छह महीने में उपचार पूरा हो जाता है और इसके दुष्प्रभाव न्यूनतम होते हैं।
- ▶ BPaL/M की सफलता दर 89% अधिक है, जबिक 2023 इंडिया टीबी रिपोर्ट में यह 68% है।
- कई देशों ने BPaL/M को अपनाया है, और अध्ययनों से पता चलता है कि यह वर्तमान उपचार की लागत का 40% से 90% तक बचा सकता है।
- BPaL/M के तत्काल कार्यान्वयन से वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को सालाना लगभग ₹6,180 करोड़ की बचत हो सकती है।

टीबी निदान में सुधार

- ▶ BPaL/M जैसे उन्नत उपचारों से लाभ उठाने के लिए रोगियों के लिए प्रारंभिक और सटीक निदान आवश्यक है।
- 🗪 त्वरित और अधिक कुशल पहचान के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षण विधियों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।



THE DOWN HINDU Daily News Analysis

★ स्वास्थ्य डेटासेट और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करने से कमज़ोर आबादी की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि सह-रुग्णता वाले, पूर्व कोविड-19 रोगी, या उच्च जोखिम वाले समुदायों (जैसे, झुग्गी-झोपड़ियाँ और जेल) में रहने वाले लोग।

सक्रिय स्क्रीनिंग का महत्व

 बहु-रोग-केंद्रित स्क्रीनिंग अभियान टीबी के मामलों का जल्द पता लगाने में मदद कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन व्यक्तियों में भी जिनमें टीबी के सामान्य लक्षण (जैसे, खांसी, बुखार) नहीं हैं।

🗪 राष्ट्रीय टीबी प्रसार् सर्वेक्षण (2019-21) से पता चलता है कि 42.6% मामलों का पता छाती के एक्स-रे के माध्यम से

लगाया गया था, जो अन्यथा छूट सकते थे।

▶ AI-संचालित उपकरणों से लैंस पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें टीबी के निदान में देरी को कम करने में मदद कर सकती हैं, खासकर दूरदराज और कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।

तीव्र निदान विधियों का विस्तार

 दवा प्रतिरोध का तेजी से पता लगाने और प्रोफाइलिंग के लिए कम संवेदनशील माइक्रोस्कोपी विधियों से तीव्र आणविक परीक्षणों की ओर स्थानांतिरत होने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

• तेज निदान विधियों से टीबी का पता लगाने की दर में सुधार होगा और बेहतर उपचार परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वे सबसे

उपयुक्त उपचारों के साथ प्रारंभिक हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं।

निष्कर्षः

- भारत में टीबी को खत्म करने के लिए BPaL/M जैसे छोटे, अधिक प्रभावी उपचारों को प्राथमिकता देना, निदान विधियों में सुधार करना और प्रारंभिक पहचान के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है।
- ये कार्य एक स्वस्थ भविष्य के निर्माण और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण निवेश हैं।

भारत में टीबी की वर्तमान स्थिति:

- ▶ घटना दर: 2022 तक, भारत में टीबी की घटना दर प्रति 100,000 जनसंख्या पर 199 मामलों की रिपोर्ट की गई, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से कम है। यह 2015 से नए टीबी मामलों में 16% की कमी को दर्शाता है।
- व्यापकता: 2019 से 2021 तक किए गए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में तपेदिक संक्रमण (टीबीआई) का अनुमानित प्रसार लगभग 31% था।
- वैश्विक योगदान: 2020 में टींबी के वैश्विक मामलों में भारत का योगदान लगभग 26% था। उस वर्ष, भारत ने एचआईवी-नकारात्मक व्यक्तियों में वैश्विक टीबी मौतों का 38% प्रतिनिधित्व किया।
- मृत्यु दर: टीबी के कारण मृत्यु दर 2015 में प्रित लाख जनसंख्या पर 28 से घटकर 2022 में प्रित लाख जनसंख्या पर 23 हो गई, जो रोग के प्रबंधन में प्रगित का संकेत है।
- कुल मामले: अनुमान बताते हैं कि भारत में टीबी के कुल मामलों की संख्या हाल के वर्षों में 2.2 मिलियन से बढ़कर 2.6 मिलियन हो गई है, जो पता लगाने और उपचार में जारी चुनौतियों को दर्शाता है।





तपेदिक क्या है?

के बारे में:

o तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक जीवाणु संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम हैं फेफड़े, फुफ्फुस (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लिम्फ नोड्स, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क।

संचरण:

o यह एक वायुजनित संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।

🟓 लक्षण:

o सक्रिय फेफड़ों के टीबी के सामान्य लक्षण हैं खांसी के साथ बलगम और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

संक्रमण का प्रसार:

o हर साल, 10 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़ते हैं। एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी होने के बावजूद, हर साल 1.5 मिलियन लोग टीबी से मरते हैं - जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा संक्रामक हत्यारा बन जाता है। o टीबी HIV से पीड़ित लोगों की मृत्यु का प्रमुख कारण है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है। o टीबी से बीमार होने वाले ज़्यादातर लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। टीबी से पीड़ित लगभग आधे लोग 8 देशों में पाए जा सकते हैं: बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका।

उपचार:

- o टीबी का इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं के मानक 6 महीने के कोर्स से किया जाता है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण और सहायता के साथ प्रदान किए जाते हैं।
- o टीबी-रोधी दवाओं का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है और सर्वेक्षण किए गए हर देश में 1 या उससे ज़्यादा दवाओं के प्रति प्रतिरोधी स्ट्रेन दर्ज किए गए हैं।
- o मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) टीबी का एक रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन, 2 सबसे शक्तिशाली, पहली पंक्ति की टीबी-रोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
- ० एमडीआर-टीबी का इलाज बेडाक्विलाइन जैसी दूसरी पंक्ति की दवाओं का उपयोग करके किया जा सकता है।
- o व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी (एक्सडीआर-टीबी) एमडीआर-टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो सबसे प्रभावी दूसरी पंक्ति की एंटी-टीबी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे अक्सर रोगियों के पास कोई और उपचार विकल्प नहीं बचता।

टीबी के लिए दवाएँ:

- o आइसोनियाज़िड (INH): यह दवा टीबी के उपचार की आधारशिला है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है।
- o यह बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड के संश्लेषण को बाधित करके काम करता है।



THE DE HINDU Daily News Analysis

o रिफैम्पिसिन (IRF): टीबी के उपचार में एक और आवश्यक दवा, रिफैम्पिसिन बैक्टीरिया में आरएनए के संश्लेषण को बाधित करके काम करता है।

• इसका उपयोग अक्सर टीबी के इलाज के लिए अन्य दवाओं के साथ संयोजन में किया जाता है और यह दवा प्रतिरोध के विकास को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

o डेलामैनिड: डेलामैनिड एक नई दवा है जिसका उपयोग मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट टीबी (एमडीआर-टीबी) के उपचार में किया जाता है और इसका उपयोग अक्सर अन्य दवाओं के साथ संयोजन में किया जाता है।

टीबी से निपटने के लिए विभिन्न पहल क्या हैं?

वैश्विक प्रयास:

- o WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) ने ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरिशप के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल "फाइंड. ट्रीट. ऑल. #एंडटीबी" शुरू की है।
- o WHO वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट भी जारी करता है।
- o टीबी को समाप्त करने की वैश्विक योजना, 2023-2030: यह 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में टीबी को समाप्त करने की एक योजना है। यह आवश्यक प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों का खाका और टीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का विस्तृत अनुमान प्रदान करता है।
- o यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य देशों ने अपनाया है।
- o टीबी को समाप्त करने की रणनीति संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.3 के संदर्भ में प्रयासों के दायरे को आगे बढ़ाती है और महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करती है।

भारत के प्रयास:

- o प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
- o क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) (2017-2025)
- o टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान
- o निक्षय पोषण योजना
- o रिपोर्ट इंडिया: रिपोर्ट इंडिया (क्षय रोग (टीबी) के लिए क्षेत्रीय संभावित अवलोकन अनुसंधान) एक द्विपक्षीय, बहु-संगठनात्मक, सहयोगात्मक प्रयास है जिसे 2013 में भारत-अमेरिका वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम (वीएपी) के तहत स्थापित किया गया था।
- o इसका उद्देश्य भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए टीबी के खतरे को दूर करना है।



Shanghai Cooperation Organization

- 2001 से एससीओ की सदस्यता का विस्तार हुआ है और वर्तमान में इसके आठ सदस्य देश हैं।
- 1996: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा 'शंघाई फाइव' की स्थापना की गई।
- ▶ 2001: 2001 में उज्बेकिस्तान को जोड़ने के बाद, शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया।
- 2015: रूस के उफा में, SCO ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया।
- 2016: भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में दायित्वों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एससीओ
 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई।
- 2017: अस्ताना में, भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए।
- 2021: यह घोषणा की गई कि ईरान SCO का पूर्ण सदस्य बन जाएगा।



सदस्य चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस,



	-	ताजिकिस्तान,	ईरान	और
	उज्बेकिस्तान			
पर्यवेक्षक	अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया			
संवाद भागीदार	आर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, श्रीलंका, तुर्की,			
	मिस्र, नेपाल, कतर	'और सऊदी अरव	ৰ	-

शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य

- SCO का मतलब है "शंघाई सहयोग संगठन"। यह 2001 में कजािकस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेिकस्तान और तािजिकस्तान द्वारा स्थािपत एक अंतर-सरकारी राजनीितक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में शंघाई, चीन में आयोजित किया गया था।
- SCO का उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा, पिरवहन और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और आपसी समर्थन को बढ़ावा देना है।
- शंघाई भावना SCO का मुख्य मूल्य है। यह आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और SCO सदस्यों के बीच आम विकास की खोज के बारे में है।
- SCO सिववालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है।

sco के मुख्य उद्देश्य हैं:

- o सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना।
- o राजनीतिक मामलों, अर्थशास्त्र और व्यापार, वैज्ञानिक-तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों के साथ-साथ ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना।
- o क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना।
- o एक लोकतांत्रिक, न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएँ।

शंघाई सहयोग संगठन का महत्व

- सहयोग के क्षेत्र: SCO ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ़ अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है।
- रणनीतिक महत्व: SCO में एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को प्राप्त करने और सीमाओं के पार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, SCO के प्रयास अपने पूरे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी को बढावा दे सकते हैं।





आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ़ सुरक्षा:

इसने न केवल आतंकवाद के खिलाफ़ बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

QUAD के साथ तुलना: SCO ने अपनी पहलों की श्रृंखला जैसे "शांति मिशन" अभ्यासों के माध्यम से साझा सैन्य और सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शित की है, जिसमें सुधारित काड अब तक सभी सदस्यों को शामिल करता है।

